शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार में
मध्यप्रदेश

निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली मामले पर सुनवाई पूरी, निर्णय सुरक्षित

निजी स्कूलों और अभिभावकों की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव

कार्यालय संवाददाता

मप्र हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इसके पूर्व निजी स्कूलों और अभिभावकों की ओर से अपने-अपने प्रस्ताव पेश किए गए। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूली पर रोक लगा दी थी।

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और अभिभावकों की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा गया है कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बाद भी निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है। इस मामले में मप्र हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और इंदौर खंडपीठ ने अलग-अलग आदेश जारी किए थे। दो अलग-अलग आदेशों से विरोधाभासी स्थिति बन गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं की मुख्य पीठ जबलपुर में एक साथ सुनवाई शुरू की। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूली पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों, अभिभावकों और अन्य पक्षों से ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा था, ताकि सभी पक्षों का हित सुरक्षित रहे। निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ गोयलाल गुप्ता ने प्रस्ताव दिया कि कोरोना काल में केवल ट्यूशन फीस ली जा रही है। सामान्य स्थिति बहाल होने और स्कूल चालू होने पर शेष फीस किश्तों में ली जाएगी। कुछ याचिकाकर्ताओं ने केवल ट्यूशन फीस लेने तो कुछ ने कोरोना काल के दौरान फीस माफी का प्रस्ताव दिया। कुछ याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रस्ताव में कहा कि हाईकोर्ट जो आदेश पारित करेगा, उसका पालन किया जाएगा। सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने निर्णय सुरक्षित कर लिया।

लीवर ट्रांसप्लांट में 60 लाख का खर्च

वीआरएस लेने के बाद भी शिक्षक को भुगतान नहीं

संवाददाता, जबलपुर। करीब दो माह पहले स्वास्थ्य कारणों के चलते वीआरएस लेने वाले पनागर संकुल में सहायक शिक्षक सत्यनारायण चौबे गंभीर बीमारी के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके लीवर ट्रांसप्लांट में करीब 60 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले स्वत्वों का भुगतान न होने से उनका इलाज प्रभावित हो रहा है। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेन्द्र दुबे, जवाहर केवट आदि ने इस मामले की शिकायत संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी से करते हुए तत्काल कार्रवाई की माँग की है, ताकि पीड़ित शिक्षक की रुकी हुई राशि का भुगतान जल्द से जल्द हो सके। गंभीर बीमारी से पीड़ित श्री चौबे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पी-2

यूजी और पीजी में 7 लाख एडमिशन होने की उम्मीद

हर स्टूडेंट को मिले प्रवेश इसलिए शासन स्तर से 15 प्रतिशत सीट में की गई वृद्धि

हरिभूमि न्यूज ▸▸ भोपाल

इस शैक्षणिक सत्र यूजी पीजी में करीब 7 लाख एडमीशन होने की उम्मीद है। कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में प्रवेश लेने से छूट न जाए इसलिए विभिन्न स्तरों पर सीटों की वृद्धि की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि शासन स्तर पर शासकीय व स्वशासी कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान की सीटों में 15 फीसदी की वृद्धि कर दी गई है। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज प्राचार्य अपने स्तर पर 30 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकते हैं।

विशेष परिस्थितियों में आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति से संचालित पाठ्यक्रमों की सीट संख्या में और भी अधिक वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी कॉलेज सीट वृद्धि के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करेंगे और वहीं की अनुमति से सीट संख्या में वृद्धि की जा सकती है। सीटों में वृद्धि के लिए पोर्टल 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक खुला रहेगा। निजी कॉलेजों के मामले में सत्यापन की कार्रवाई 12 तक होगी।

कॉलेज प्राचार्य अपने स्तर पर 30% और आवश्यकता पड़ने पर आयुक्त उच्च शिक्षा के माध्यम से और बढ़ा सकेंगे सीट

कॉलेजों का विकल्प दोबारा चुनने का मिलेगा अवसर

पाठ्यक्रम चुनने के लिए 5 अक्टूबर से पोर्टल फिर से खोला जाएगा। पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए कॉलेजों का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। जहाँ अभ्यर्थियों के पंजीयन और विकल्प चुनने तथा अभ्यर्थन का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें 12वीं सप्लीमेंटरी के बाद पास हुए और उनके अंकों वाले छात्रों के लॉगिन प्रारंभ शामिल हैं। नया अभ्यर्थियों को प्रोफाइल पंजीयन तथा अभ्यर्थन का पूरा अवसर मिलेगा। सूचना पोर्टल पर सीटों का प्रकाशन किया जाएगा।

यूजी के सेकंड राउंड सीएलसी में प्रवेश का आज अंतिम दिन, पीजी के लिए जारी होगी मेरिट

यूजी में प्रवेश के लिए अंतिम [illegible] है। इसमें [illegible] अक्टूबर को एडमिशन होंगे। यूजी के [illegible] अभ्यर्थियों [illegible] अक्टूबर से [illegible] है। इसमें [illegible] अक्टूबर को एडमिशन लिया है। प्रवेश [illegible] अभ्यर्थियों [illegible] अक्टूबर तक एडमिशन ले रहे हैं। वहीं पीजी में एडमिशन के लिए [illegible] अक्टूबर [illegible] के अनुसार [illegible] अभ्यर्थियों को [illegible] अक्टूबर को एडमिशन लिया है। अभ्यर्थियों को [illegible] के बाद [illegible] अक्टूबर को [illegible] सीटों का प्रकाशन किया जाएगा।

कांग्रेस ने कभी पीएससी कर नियमित करने का काम नहीं किया

[illegible]

यूजी और पीजी स्तर पर तृतीय चरण की सीएलसी का कार्यक्रम

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए

- [illegible] अक्टूबर [illegible] अक्टूबर [illegible]।
- [illegible] सीटों [illegible] अक्टूबर को जारी [illegible] जाएगी।
- [illegible] अक्टूबर [illegible] अक्टूबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा।

स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए

- [illegible] अक्टूबर [illegible] अक्टूबर [illegible]।
- [illegible] सीटों [illegible] अक्टूबर को जारी [illegible] जाएगी।
- [illegible] अक्टूबर [illegible] अक्टूबर तक प्रवेश लिया जा सकेगा।

एक लाख विद्यार्थियों के लिए आज से कालेजों में फिर शुरू होगा प्रवेश का सिलसिला

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। उच्च शिक्षा विभाग की यूजी और पीजी कक्षाओं में प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। प्रवेश प्रक्रिया बुधवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर तक चलेगी। विद्यार्थियों के लिए कालेजों में प्रवेश का यह अंतिम अवसर रहेगा।

विभाग का मानना है कि अब भी करीब 10 से एक लाख विद्यार्थी हैं जो कालेजों में प्रवेश से वंचित हैं। उनमें स्कूल शिक्षा विभाग की कक्षा 12वीं और एक साल नहीं योजना में पास हुए विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा विभाग ने कालेजों की मौजूदा सीटों में 15 फीसद का इजाफा कर दिया है। अब जिन कालेजों में सीटें भर जाने के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा था उसे निर्णय के बाद मिल सकेगा। इसी तरह 30 फीसद तक सीटें बढ़ाने का अधिकार संबंधित कालेज के प्राचार्य के पास रहेगा। इससे ज्यादा सीटें बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा आयुक्त की अनुमति लेनी होगी।

यूजी के द्वितीय, तृतीय वर्ष की कक्षाओं में होंगे आनलाइन प्रवेश

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग के निजी और सरकारी कालेजों की यूजी के द्वितीय, तृतीय वर्ष समेत पीजी के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं में भी इस साल आनलाइन ही प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश की प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो जाएगी। अब तक कालेजों में एक ही बार प्रवेश लेना होता था। पास होने के बाद अगली कक्षाओं में प्रवेश अपने आप हो जाता था। अधिकारियों का कहना है कि एक बार प्रवेश के बाद विभाग को जानकारी ही नहीं होती थी कि अगली कक्षा में कितने विद्यार्थी पहुंचे। इस वजह से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। अगली कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को नतीजे जारी होने के बाद पोर्टल के जरिए लागिन करना होगा। विद्यार्थी जैसे ही नामांकन क्रमांक और जन्मतिथि डालेंगे, उनकी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। इसके बाद अगली जिस कक्षा और कालेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, उसकी जानकारी देनी होगी। जानकारी दर्ज करने के बाद पंजीकृत मोबाइल पर प्रवेश की पुष्टि का मैसेज आएगा।

नौ से यूजी में प्रवेश के लिए रजिस्ट्री : यूजी कक्षाओं में तीसरे दौर की कालेज स्तरीय काउंसिलिंग नौ अक्टूबर से शुरू होगी। कालेज के आवंटन 10 को होगा। 26 अक्टूबर तक आनलाइन फीस जमा कर आवंटित कालेज में प्रवेश ले सकेंगे। इसी तरह पीजी में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन 14 अक्टूबर से शुरू होगी। 24 अक्टूबर को कालेज के आवंटन कर दिया जाएगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोनावायरस संक्रमण का प्रसार थमा नहीं है। रोजाना बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने अब अनलॉक 5 की गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत राज्यों को स्कूल खोलने और बंद करने का अधिकार दिया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला बरकरार रखा है। केंद्र की गाइडलाइन जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि 15 अक्टूबर से राज्य में स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि सभी स्कूल प्रमुखों और अभिभावकों से सहमति लेने के बाद ही तय होगा कि स्कूल खोला जाए या नहीं। दूसरी ओर स्कूल खोलने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था चलती रहेगी। बता दें कि कोरोना के बीच अनलॉक-5 के तहत शिक्षा मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में राज्यों को अधिकार दिए हैं कि वे अपने स्तर पर चर्चा कर स्कूल को खुलने का आदेश दे सकते हैं।

कोर्ट ने भर्ती हुए 17 शिक्षकों की जांच 8 सप्ताह में खत्म करने का दिया आदेश

ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में नियमों को तक पर रखकर भर्ती किए गए 17 शिक्षकों के मामले की जांच सीआइडी को 8 सप्ताह में खत्म करने के आदेश दिए हैं। युगल पीठ ने एकल पीठ के फैसले में बदलाव किया है। कार्य परिषद में प्रस्ताव पारित होने के बाद तत्कालीन कार्य परिषद सदस्य राजेन्द्र सिंह यादव ने 22 अगस्त 2016 में सीआइडी को शिकायत की थी। इस मामले में चार साल में सीआइडी ने कोई जांच नहीं की है, इसलिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जीवाजी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2011 से 2013 के बीच 17 प्रोफेसरों की नियुक्तियां की गई थी। इन नियुक्तियों में योग्यता व नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया और गलत तरीके से प्रोफेसरों की नियुक्ति कर दी। इस मामले की शिकायत राज्य शासन को की गई, लेकिन सरकार ने इन नियुक्तियों की कोई जांच नहीं कराई। कार्य परिषद में सीबीआई व सीआइडी से जांच का प्रस्ताव पारित किया गया था। मामला सीआइडी को भेजा गया, लेकिन सीआइडी ने भी मामले की जांच नहीं की। इसके बाद राजेन्द्र सिंह ने जांच को लेकर हाई कोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी।

अनलॉक-5 की गाइड लाइन में 15 अक्टूबर के बाद खुल सकेंगे शैक्षणिक संस्थान

कहीं छात्रावास बने कोविड सेंटर तो कहीं पर चल रहा रेनोवेशन का काम, आखिर कहां रहेंगे बाहर से आने वाले छात्र-छात्राएं

[illegible]

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का छात्रावास भी 27 मार्च से है बंद

कोविड सेंटर से होगा विवाद

[illegible]

राजधानी के होस्टलों की यह है स्थिति

बीयू भोपाल [illegible]

आरजीपीवी [illegible]

मैनिट [illegible]

गीताजली कॉलेज [illegible]

फीजिकल क्लास जल्द नहीं होगी शुरू

[illegible]

कंपल्सन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं

[illegible]

शासन की ओर से नहीं मिला आदेश

[illegible]

दर्जनों प्राइवेट होस्टल बंद, किराए का लेना होगा कमरा

[illegible]

एमबीए, एमसीए काउंसलिंग शुरू

भोपाल। एमबीए, एमसीए कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। अभी एनआरई छात्रों के लिए आरक्षित सीटों पर एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन प्रक्रिया 14 अक्टूबर तक चलेगी। प्रदेश के छात्रों के एडमिशन की के लिए शैड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इसके बाद एडमिशन प्रक्रिया नवंबर तक चलेगी।

बीयू में ऑनलाइन क्लास के लिए प्रशिक्षण शुरू

नसं, भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा बीयूआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं के सफल संचालन के लिए शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार से फैकेल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम 8 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम में यूआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज गौर विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं डीन प्रोफेसर केबी पंडा, कोर्स कोऑर्डिनेटर सुनंदा मानकी और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर एसके राव ने कहा कि कोविड-19 के इस दौर में शिक्षकों को वर्चुअल रूप से ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन में किसी तरह की असुविधा ना हो तथा छात्र हित में कक्षाओं का संचालन सुचारु रूप से संचालित हो पाए।

एडमिशन के लिए चलाया जाएगा अतिरिक्त राउंड

सरकारी, आटोनॉमस कॉलेजों में यूजी-पीजी की 15% सीटें बढ़ीं

पीपुल्स संवाददाता ○ भोपाल

मो.नं. 9893231237

प्रदेश के सरकारी और ऑटोनोमस कॉलेजों में यूजी-पीजी कोर्स में 15 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा प्राचार्य जरूरत के अनुसार संसाधनों एवं सुविधा के अनुसार सीटों में 30 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों में सीटों की वृद्धि के लिए 7 से 12 अक्टूबर तक पोर्टल खोला जाएगा। यूजी-पीजी में एडमिशन से वंचित स्टूडेंट्स के लिए तीसरा अतिरिक्त सीएलसी राउंड चलाया जाएगा।

यह घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए की। मंत्री ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों में एडमिशन के लिए 5 अगस्त से काउंसलिंग शुरू की गई थी। यूजी में एडमिशन 7 अक्टूबर को सेकंड सीएलसी राउंड के साथ समाप्त हो रहा है। लेकिन कई स्टूडेंट्स किन्हीं कारणों से एडमिशन नहीं ले पाए हैं। इसके अलावा हाल ही में 'रुक जाना नहीं' एवं सप्लीमेंट्री के एग्जाम में लगभग 1 लाख 12 हजार स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इनके यूजी में एडमिशन की जिम्मेदारी सरकार की है। चूंकि अधिकतर सरकारी कॉलेजों में सीटें फुल हो चुकी हैं, इसलिए सरकार कॉलेजों में सीटें बढ़ा रही है। इसमें 15 प्रतिशत तो शासन स्तर पर सीटें स्वतः बढ़ जाएंगी। इसके बाद यदि कोई कॉलेज अपने स्तर पर सीट वृद्धि करना चाहता है, तो 7 से 12 अक्टूबर तक खुलने वाले पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

तीसरा सीएलसी राउंड

- **9 अक्टूबर:** यूजी में रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन व चॉइस फिलिंग
- **19 अक्टूबर:** कॉलेजों द्वारा मेरिट लिस्ट का प्रकाशन
- **19 से 26 अक्टूबर:** ऑनलाइन शुल्क जमा कर एडमिशन
- **14 अक्टू. से:** पीजी में रजिस्ट्रेशन, वेरीफिकेशन व चॉइस फिलिंग
- **24 अक्टूबर:** कॉलेजों द्वारा मेरिट लिस्ट का प्रकाशन
- **24 से 29 अक्टूबर:** ऑनलाइन शुल्क जमा कर एडमिशन

निजी कॉलेजों में बढ़ाई जा सकेंगी सीटें

निजी या अनुदान प्राप्त कॉलेज अपनी यूजी-पीजी की सीटें बढ़ाना चाहते हैं, तो संबंधित विश्वविद्यालय को आवेदन कर सीट बढ़ा सकते हैं। संबंधित विवि 12 अक्टूबर तक वेरीफिकेशन कर इसकी अनुमति देंगे।

दोबारा होगी चॉइस फिलिंग

सीएलसी का तीसरा अतिरिक्त राउंड 9 अक्टूबर से शुरू होगा। इसमें रुक जाना नहीं और सप्लीमेंट्री के पास नए स्टूडेंट तो रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग व वेरिफिकेशन कराएंगे। जो स्टूडेंट्स पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, वे चॉइस फिलिंग कर मनपसंद कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे। सभी आवेदकों को प्रोफाइल एडिट करने व वेरिफिकेशन को दोबारा मौका दिया जाएगा। तीसरे सीएलसी राउंड में एडमिशन कॉलेजों द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार होगा।

यूजी में सीएलसी राउंड का आज अंतिम दिन

भोपाल। यूजी में प्रवेश के लिए सेकंड सीएलसी राउंड चल रहा है। 7 अक्टूबर तक एडमिशन होंगे। इस राउंड में 2,08,487 स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग की है। 60,221 ने एडमिशन लिया है। वहीं पीजी में 98,975 स्टूडेंट को चॉइस के अनुसार सीट आवंटित की गई थी। इनमें से 12,201 ने एडमिशन ले लिया है। इधर, एनसीटीई के अंतर्गत बीएड सहित आठ कोर्स में प्रवेश के लिए 5808 ने पंजीयन और 4305 ने सत्यापन कराया है। सत्यापन की आज अंतिम तारीख है।

ऑनलाइन जैव विविधता प्रतियोगिता आयोजित

दतिया ब्यूरो

मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जैव विविधता प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन किया गया। वन विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वन मंडल अधिकारी दतिया श्रीमती प्रियांशी सिंह राठौड़ एवं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिसमें दतिया जिले का बेहतर प्रदर्शन रहा। जिला स्तरीय क्विज मास्टर शैलेश खरे ने बताया कि दो चरणों में आयोजित इस प्रतियोगिता में पहले चरण में 102 विद्यालयों की पंजीकृत टीमों ने सहभागिता की। जिसमें से सात टीमों की द्वितीय चरण हेतु चयन किया गया। द्वितीय चरण में सम्मिलित 7 टीमों में से प्रथम स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय बीकर, द्वितीय स्थान पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उनाव तथा तृतीय स्थान पर शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय सेंवढ़ा ने प्राप्त किया। वन परिक्षेत्र अधिकारी नीरज परिहार ने बताया कि प्रथम स्थान प्राप्त टीम को 3000, द्वितीय स्थान 2100 एवं तृतीय स्थान प्राप्त टीम को 1500 के पुरस्कार दिए जाएंगे तथा प्रथम स्थान प्राप्त राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सहभागिता करेगी।

वर्चुअल क्लासेस में शिक्षकों की परेशानियों का ध्यान रखें

बीयूआईटी में दी ऑनलाइन क्लासेस की ट्रेनिंग

बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षण के दौरान संबोधित करते हुए अधिकारी।

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल

editor@peoplessamachar.co.in

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) के आईटी के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं सुचारु संचालित करने विवि शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों का तीन दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम मंगलवार से शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रो. आर.जे. राव ने किया। बीआईटी के डायरेक्टर प्रो. नीरज गौर विवि के भाषा विज्ञान के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं डीन प्रो. कीर्ती पंडा कोर्स को-ऑर्डिनेटर सुनंदा मानकी व शिक्षक इस मौके पर उपस्थित थे। कुलपति प्रो. राव ने कहा कि कोविड-19 के दौर में शिक्षकों को वर्चुअली ऑनलाइन कक्षाओं में असुविधा न हो तथा छात्र हित में संचालन सुचारु हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कर्मचारियों और ऑफिसर्स को कंप्यूटर के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण हुए, इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इस अवसर पर नीरज गौर ने कहा कि विवि के शिक्षक व अतिथि विद्वानों को ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। प्रशिक्षण में करीब 50 फैकल्टी मेंबर्स जिसमें अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, अंग्रेजी, मैनेजमेंट, वाणिज्य, प्रौढ़ शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं आईओ डीई के शिक्षकों ने ऑनलाइन टीचिंग की जानकारी ली। कार्यक्रम के दूसरे दिन बुधवार को विवि के शेष विभागों तथा समाजशास्त्र समाज कार्य मनोविज्ञान रीजनल प्लैनिंग एंड इकोनामिक ग्रोथ इत्यादि के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जैव विविधता प्रतियोगिता में प्रथम रही संस्कार की टीम

भिण्ड ब्यूरो

वन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश जैव विविधता विषय पर आयोजित लिखित परीक्षा में आईपीएस स्कूल के छात्र संस्कार शर्मा और उनकी टीम के छात्र अजय पाराशर एवं भरत सिंह ने 90 में से 85 अंक प्राप्त कर न केवल भिण्ड जिले में अपितु मध्यप्रदेश के 53 जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिला और स्कूल का मान बढ़ाया है। यहां बता दें कि संस्कार शर्मा पुत्र हरनारायण शर्मा एडवोकेट ने पिछले वर्ष भी आईपीएस स्कूल का नेतृत्व करते हुए भिण्ड जिले में प्रथम स्थान पाया था और राज्य स्तर पर भिण्ड जिले का नेतृत्व किया था।

कंटेनर ने मारी टक्कर, पुलिस घटना की जांच में जुटी

शिक्षक संघ के संगठन मंत्री का सड़क दुर्घटना में निधन, पत्नी घायल

ग्वालियर, न.सं.

जिले में भारी वाहन चालकों की लापरवाही के कारण राहगीरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। मंगलवार को कैंसर पहाड़ी पर एक चालक ने अंधाधुंध गति से कंटेनर को चलाते हुए एक्टिवा सवार वरिष्ठ स्वयंसेवक एवं शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संगठन मंत्री भारत सिंह चौहान को अपनी चपेट में ले लिया। जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार ग्राम दतहरा थाना माता बसैया जिला मुरैना निवासी भारत सिंह पुत्र मुरलीसिंह चौहान उम्र 78 वर्ष मंगलवार को अपनी पत्नी श्रीमती मनोरमा चौहान उम्र 70 वर्ष के साथ भितरवार से एक्टिवा पर सवार होकर निकले थे। बताया गया है कि मृतक भारत सिंह का बेटा धर्मेन्द्र चौहान भितरवार में शिक्षक है। सुबह साढ़े दस बजे के करीब वृद्ध दम्पति झांसी रोड थाना क्षेत्र स्थित कैंसर पहाड़िया के पास मोड़ पर पहुंचे ही थे कि तभी शिवपुरी लिंक रोड की ओर से आ रहे कंटेनर क्रमांक एचआर 55 एडी 2735 के चालक ने तेज व लापरवाही से गाड़ी को चलाते हुए एक्टिवा में टक्कर मार दी। जिसमें वह कंटेनर के नीचे आ गए और मौके पर ही भारत सिंह की मौत हो गई। जबकि उनकी पत्नी मनोरमा गंभीर रूप से घायल हो गईं। झांसी रोड थाना प्रभारी पंकज त्यागी का कहना है कि भारत सिंह कैंसर पहाड़िया की ओर जा रहे थे। कंटेनर चालक ने दूसरी दिशा में आकर वृद्ध दम्पति को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल श्रीमती मनोरमा चौहान को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कंटेनर में दो पहिया वाहन भरे हुए थे और चालक बैंगलोर से कंटेनर लेकर दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर घटना की विवेचना प्रारंभ कर दी है। यहां बता दें कि बाल्यकाल से स्वयंसेवक मृतक भारत सिंह चौहान शिक्षक संघ के जिला प्रमुख, प्रदेश सचिव जैसे दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में उनके पास छत्तीसगढ़ प्रांत के संगठन मंत्री का दायित्व था। उनकी पुत्री श्रीमती ममता भदौरिया नगर पालिका भिण्ड की अध्यक्ष रही हैं। उनके छोटे भाई लाखन सिंह चौहान विद्या भारती के विभाग समन्वयक रह चुके हैं।

स्नातक में प्रवेश से वंचित रह गए कई छात्र

प्रवेश प्रक्रिया आज होगी समाप्त, एक और मौका देने की मांग

जागरण, रीवा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) का आखिरी चरण बुधवार को समाप्त हो जायेगा। इसके बाद भी महाविद्यालयों की अधिकाधिक सीट रिक्त होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा होने पर उच्च शिक्षा विभाग प्रवेश के लिए सीएलसी का एक और चरण कार्यक्रम जारी कर सकता है। गौरतलब है कि सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया इस बार विभाग ने एक महीने की देरी से शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत एक चरण ऑनलाइन प्रवेश का व दो चरण सीएलसी के हो चुके हैं। विभाग ने कोरोनाकाल के चलते प्रवेश की पूरी गतिविधि ऑनलाइन संचालित करने की व्यवस्था बनाई थी परंतु सर्वर फेल रहने व अन्य तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह व्यवस्था फेल हो गई। वहीं, कई बच्चों को अभी भी महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाया है। लिहाजा छात्र संगठनों द्वारा एक बार और प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई जा चुकी है, जिस पर फिलहाल विभाग ने कोई निर्णय नहीं किया है।

पीजी में प्रवेश के लिए दूसरी सीएलसी आज से

इधर, स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन सीएलसी का दूसरा चरण बुधवार से शुरू होगा। यह प्रक्रिया 12 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रक्रिया में विभाग से ऑनलाइन मेरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय छात्रों को प्रवेश देंगे। छात्र सरकारी या गैर सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेते वक्त पहली किस्त के तौर पर 1 हजार रूपये जमा कर सकेंगे। प्रवेश शुल्क की शेष राशि छात्रों को आगामी माह में दो किस्तों में जमा करनी होगी। छात्र चाहें तो एकमुश्त भी प्रवेश शुल्क जमा कर सकते हैं। इस निर्देश का पालन करने के लिए विभाग ने निजी महाविद्यालयों को भी कहा है। इस तरह प्रवेश शुल्क की तीनों किस्त छात्रों को ऑनलाइन ही देनी होगी। ई-प्रवेश पोर्टल पर छात्रों को ऑनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा दी गई है। छात्र एटीएम, डेबिट कार्ड या अन्य डिजीटल तरीके से शुल्क जमा कर सकेंगे। शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर छात्र का प्रवेश संबंधित महाविद्यालय की प्रवेश सूची में दर्शित होगा। किसी भी तरह से ऑफलाइन का भुगतान विभाग ने स्वीकार नहीं किया है। सम्भवतः अक्टूबर में महाविद्यालय खुलने के बाद छात्रों को मूल टीसी व माइग्रेशन आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।

द्वितीय, तृतीय वर्ष में प्रवेश अगले माह : स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की कक्षाओं में पावधिक प्रवेश नवम्बर माह में होगा। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने सूचना जारी कर दी है। प्रवेश हेतु विधिवत गाइडलाइन विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जायेगी। इन कक्षाओं के छात्रों का प्रवेश भी पूरी तरह ऑनलाइन होगा। महाविद्यालयों की प्रवेश समिति पोर्टल में छात्रों को प्रमोट करेगी। प्रमोट विकल्प में नामांकन दर्ज करते ही छात्रों का पूरा विवरण अगली कक्षा की प्रवेश सूची में दर्ज हो जायेगा। इसके उपरांत छात्रों को प्रवेश शुल्क जमा करनी होगी। पहली किस्त में छात्र 500 रूपये शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकेंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने के बाद छात्रों को पोर्टल से प्राप्त रसीद या प्रिंट आउट लेना होगा, जो महाविद्यालय खुलने पर दस्तावेज सत्यापन के समय छात्रों को देना होगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के चक्कर में सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया एक माह देरी से शुरू हुई। नव प्रवेश के अलावा अब पहले से प्रवेशित छात्रों को अगली कक्षा में भेजने में भी अब समय लग रहा है।

शिक्षक संघ की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

कुन्डम। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की ब्लाक स्तरीय बैठक का आयोजन महावीर कुन्डम के परिसर में किया गया। बैठक की अध्यक्षता शक्कुमार चौबे जिला अध्यक्ष, मुख्य आतिथ्य गोविंद बिसेन प्रांतीय संघठन मंत्री, विशिष्ट आतिथ्य डी.के. विश्वकर्मा संभागीय अध्यक्ष ने की। कार्यक्रम का संचालन विवेक तिवारी ब्लाक अध्यक्ष ने किया! बैठक मे अध्यापकों की स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं, पुरानी पेंशन, कार्यकारिणी का पुनर्गठन कर संघ को मजबूती प्रदान करने और आजीवन सदस्यता अभियान को बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न अध्यापकों ने अपने संकुल मे आने वाली वेतन संबधी समस्याओं और अन्य समस्याओं पर विचार व्यक्त किया। बैठक के दौरान गोविंद बिसेन ने मिथलेश पुरी गोस्वामी को प्रांतीय सह संघठन मंत्री नियुक्त किया जबकि डी. के विश्वकर्मा जी ने नारायण साहू को संभागीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान देवेंद्र सिंह राजपूत, सोमा चौधरी आदि उपस्थित रहे।

हाशिए पर स्वशासी महाविद्यालय का प्रस्ताव

विवि ने मूल्यांकन के लिए थोप दीं डेढ़ लाख उत्तरपुस्तिकाएं

भास्कर न्यूज

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कराई गई ओपन बुक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब शासकीय स्वशासी महाविद्यालय में ही होगा। महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय को स्टाफ की कमी और काम का अतिरिक्त भार होने का पत्र भेजा गया था। यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार ने मंगलवार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा जिले के समस्त कॉलेजों की लगभग डेढ़ लाख उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जबरन स्वशासी महाविद्यालय पर थोप दिया है। महाविद्यालय से जुड़े जानकार बताते हैं कि शासन स्तर पर सिर्फ उत्तरपुस्तिकाओं के संकलन की जिम्मेदारी दी गई थी। अब स्थिति किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रबंधन के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वह तय समय-सीमा में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर सके।

खाली करनी पड़ गई गाड़ी

स्वशासी महाविद्यालय द्वारा भेजे गए पत्र के बाद मंगलवार को विश्वविद्यालय से उत्तरपुस्तिकाओं को लेने के लिए गाड़ी भेजी गई थी, जिसमें सभी कॉलेजों की उत्तरपुस्तिकाएं लोड कराई गईं। शाम होते-होते विश्वविद्यालय से फोन आया कि मूल्यांकन स्वशासी महाविद्यालय में ही होगा। इसके बाद लोड हो चुकी उत्तरपुस्तिकाओं को वापस अनलोड किया गया और विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई गाड़ी बगैर कापियों के ही सीवा के लिए रवाना हो गई।

• 132 प्राध्यापकों का है स्टाफ स्वशासी महाविद्यालय में 55 नियमित प्राध्यापक एवं शेष अतिथि विद्वान कार्यरत हैं। इतने सीमित स्टाफ पर भोजमुक्त विश्वविद्यालय, डीएसी की परीक्षा, छात्र-छात्राओं के एडमीशन के साथ-साथ ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की जिम्मेदारी उस पर भी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा डेढ़ लाख उत्तरपुस्तिकाओं का अतिरिक्त भार डाल दिया है।

• 30 तक पूरा करना है कार्य ओपन बुक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 30 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनौतीपूर्ण इस काम को पूरा करने के लिए महाविद्यालय द्वारा दूसरे कॉलेजों से प्राध्यापकों को बुलाकर मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने की रणनीति बनाई जा रही है।

इनका कहना है

विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया है कि अगर सभी अशासी महाविद्यालय मूल्यांकन के लिए हाथ खड़े कर देंगे तो कापिया कहा जांची जाएगी, इसलिए विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन महाविद्यालय में ही कराने का निर्णय लिया गया है।

नीरजा खरे, प्राचार्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के टास्क फोर्स सदस्यों ने की चर्चा

सिटी रिपोर्टर, सतना

नवीन शिक्षा नीति की क्रियान्वयन समिति के टास्क फोर्स समिति के 23 सदस्यों की बैठक में कई मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव की अध्यक्षता में नवगठित समिति के सदस्यों ने मप्र में आगामी वर्षों में नवीन शिक्षा कैसे होगी, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों तथा वर्तमान वातावरण के देखते हुए बेहतर एवं सुनियोजित तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित किए जाने की महती आवश्यकता है। इस दिशा में स्वशासी, निजी व शासकीय विवि को उपर्युक्त तरीके से सामंजस्य कर शोध को बढ़ावा देना होगा।

श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रस्तुत नवीन शिक्षा नीति के दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त होंगे। इस मौके पर मप्र शासन के प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने सदस्यों का स्वागत किया और नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत 8 प्रमुख बिन्दुओं पर प्राथमिकता से चर्चा होगी। कार्यक्रम में एकेएस विवि के प्रतिकुलपति डॉ. हर्षवर्धन जो समिति के सदस्य हैं ने कहा कि आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिदृश्य में ग्राम इंरोलमेंट रेशियो एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रमुखता देने के दृष्टिकोण से प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में स्किल डेवलेपमेंट सेंटर विकसित करने में शासन सहयोग करें। जिन विश्वविद्यालयों में आईटी की अच्छी अधोसंरचना उपलब्ध है, उन विवि को व्यापक हित में ओपन डिस्टेंस लर्निंग व ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को आयोजित करने की अनुमति दी जाए।

उन्होंने आगे कहा कि बेहतर होगा कि पब्लिक व प्रायवेट यूनिवर्सिटीज का भेद समाप्त करते हुए अधोसंरचना विकास हेतु वर्ल्ड बैंक और रूसा के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के विकास हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाए और समस्त विवि को यूनिवर्सिटी के नाम से संबोधित किया जाए जैसा कि विश्व के विभिन्न देशों में प्रचलन है, लिबरल आर्टस और वैल्यू बेस्ड एज्यूकेशन की महती आवश्यकता है।

डॉ. हर्षवर्धन ने इंडस्ट्री-एकेडेमिया इंटरेक्शन, इंटर्नशिप, बहुआयामी रिसर्च के आधार पर उत्पादन में प्रो. एडीएन बाजपेयी, प्रो. कपिलदेव मिश्रा, एसएन मिश्रा, वरूण गुप्ता, रघुराज तिवारी, उमाशंकर पचौरी, उमेश हुलानी, डॉ. अशोक ग्वाल, डॉ. एसके जैन की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र शुक्ला ने किया।

शिक्षा नीति पर ऑनलाइन व्याख्यान श्रृखंला का आयोजन

भोपाल। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल में कल 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक तीन दिवसीय ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा नीति 2020 पर आधारित इस व्याख्यान माला का विषय भारतीय शिक्षा प्रणाली परिवर्तन की राह पर अग्रसर है। कार्यक्रम के संयोजक और कॉलेज के प्रिंसीपल नौशद हुसैन ने बताया कि गत 29 जुलाई को केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। इस शिक्षानीति को समझना और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच इसको लेकर समझ पैदा करना समय की मांग है। कॉलेज ऑफ एजुकेशन का संबध शिक्षकों से है, इसलिये हमारी जिम्मेदारी है, कि नई शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ना सिर्फ खुद समझें बल्कि उस पर शिक्षाविदों एंव विषय विशेषज्ञों की राय जानें। ताकि इस शिक्षा नीति के क्रियांवयन में शिक्षक अपनी महती भूमिका निभा सकें। वहीं इस ऑनलाइन कार्यक्रम की समन्वयक डॉ. तलजीम फातिमा नकवी ने बताया कि, श्रृखंला में देशभर के जाने माने शिक्षा विशेषज्ञों व शिक्षाविदों द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किये जांएगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए नई राह एनईपी विषय पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन 8 अक्टूबर को एनसीईटी, नई दिल्ली के पूर्व चैयरपर्सन प्रोफेसर मोहम्मद अख्तर सिद्दकी नई शिक्षा नीति के संदर्भ में टीचर एजुकेशन पर प्रकाश डालेंगे। यह आयोजन सुबह 10 से 11 बजे तक होगा। वहीं 9 अक्टूबर को पीएसएससीआईव्हीई, भोपाल के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर राजेश पी. खंवायत सुबह 10.00 से 11.30 तक नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। 10 अक्टूबर को जामिया मिल्लया इस्लामिया नई दिल्ली के प्रोफेसर फुरकान कमर हायर एजुकेशन पर सेशन को संबोधित करेंगे। जबकि 11 अक्टूबर को सीईएमसीए नई दिल्ली के सीनीयर प्रोग्राम ऑफीसर डॉ मनस राजन तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्री शिक्षा नीति के संबध में अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस सीरीज के आयोजन में एमएएनयूयू के वाइस चांसलर प्रो. एस एम रहमतुल्लाह, प्रो. एस एम महमूद भी जुड़े हैं। कार्यक्रम के समन्वयक डॉ इंद्रजीत दत्ता ने बताया कि, नई शिक्षा नीति देश के विकास को किस तरह गति देगी, इसकी विस्तार से जानकारी इस आयोजन में शिक्षा और प्रशिक्षण से जुड़े लोगों को मिलेगी।

वन विहार में गुलाबी शिविर का आयोजन

बच्चों ने सीखा रंगीन कागज पर पक्षी तितली और फूलों की आकृति बनाना

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राज्यस्तरीय वन्य-प्राणी सप्ताह के छठवें दिन मंगलवार को 38 स्कूली बच्चों को सृजनात्मक कार्यशाला में रंगीन कागज पर विविध प्रकार के पक्षियों, तितलियों एवं फूलों की आकृतियां बनाना सिखाया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के मूर्तिकार अरविंद अनुपम द्वारा पेपरमेशी के माध्यम से सारस पक्षी बनाना सिखाया गया। इसके अलावा औबेदुल्लागंज वन मंडल की वमनई समिति के विशेषज्ञों ने मुखौटा बनाना सिखाया। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में महिलाओं के लिए शिविर में कई तरह की कलाकृतियां दिखीं।

वन मंत्री शाह करेंगे वन्य-प्राणी सप्ताह का समापन

वन मंत्री विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में वन्य प्राणी सप्ताह 2020 का समापन आज सुबह 9.30 बजे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में होगा। वन मंत्री शाह वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत सम्पन्न हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही वन्य प्राणी संरक्षण में वर्ष 2019 एवं 2020 में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाएगा।

अगले साल से विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन टेस्ट

नई दिल्ली (ब्यूरो)। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तर्ज पर अब विश्वविद्यालयों में स्नातक के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी संयुक्त परीक्षा होगी। इसकी शुरुआत अगले साल यानी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से होगी। हालांकि, शुरू में इनमें सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ही शामिल किया जाएगा। लेकिन, आने वाले वर्षों में इनमें सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को शामिल किया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की सिफारिश करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। वैसे भी मंत्रालय इन दिनों नीति के सुझावों को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। एनटीए से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक योजना पर तेजी से काम चल रहा है। राज्यों के साथ भी चर्चा की जा रही है। हालांकि, इसमें स्वायत्त उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ा जाएगा या नहीं, इसे लेकर एनटीए अभी चुप है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक, एनटीए की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने के बाद सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया जाएगा। मौजूदा समय में देश में एक हजार से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। इनमें 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

व्यवस्था में बदलाव

- **शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपा जिम्मा**
- **स्नातक के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की बदलेगी व्यवस्था**

साल में दो बार हो सकती है प्रवेश परीक्षा

मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट साल में दो बार हो सकता है। यह ठीक जेईई मेंस की तरह होगा। इसमें पहली परीक्षा जनवरी या फरवरी में हो सकती है, जबकि दूसरी परीक्षा अप्रैल या मई में हो सकती है। इनमें से जिस परीक्षा में सबसे ज्यादा स्कोर होंगे, उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी। फिलहाल प्रवेश परीक्षा की रूपरेखा तैयार करने का काम चल रहा है। इनमें एक सामान्य परीक्षा के साथ विषयवार यानी कला, विज्ञान या वाणिज्य जैसे विषयों के लिए अलग से टेस्ट की भी योजना है।

अनदेखी • माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक और कारनामा, सीएम से शिकायत

कापी बदलने से 12वीं में छात्रा की आई सप्लीमेंट्री, जांच के बाद पास

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक और कारनामा सामने आया है। मंडल ने 12वीं के कामर्स संकाय की छात्रा की कापी ही बदल दी। इस बदलाव में छात्रा को एक विषय में सप्लीमेंट्री पास करना आ गई, जिस कारण वह दो महीने तक तनाव में रही।

कामर्स की छात्रा यामिनी शर्मा ने इस साल सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकंडरी स्कूल से 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। उसका अकाउंटेंसी विषय में सप्लीमेंट्री आई थी। इस विषय में उसे केवल 20 नंबर मिले थे। छात्रा को विश्वास था कि उसे इतने कम नंबर नहीं मिल सकते। बेटी के भविष्य को देखकर पिता महेश शर्मा ने मंडल में पुनर्गणना और उत्तरपुस्तिका देखने के लिए आवेदन किया। महेश शर्मा के मुताबिक यामिनी को जो उत्तरपुस्तिका मिली, वह उसकी थी ही नहीं। कापी में हस्ताक्षर, परीक्षा कक्ष क्रमांक से लेकर परीक्षा की तारीख तक गलत थी। पिता की शिकायत पर मंडल ने जांच की तो छात्रा को द्वितीय श्रेणी में पास कर दिया। अब महेश शर्मा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय सिंह परमार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पुलिस महानिदेशक से की है। उन्होंने लापरवाही करने वाले मंडल के कर्मचारियों-अधिकारियों पर एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही छात्रा को कॉलेज में प्रवेश दिलाने की भी मांग की है, क्योंकि कॉलेज में प्रवेश की तारीख लगभग निकल चुकी है।

मंडल द्वारा छात्रा को भेजी गई 12वीं अकाउंटेंसी की गलत उत्तरपुस्तिका। • **छात्रा द्वारा उपलब्ध कराए गए फोटो**

पेपर दिया 10 जून को, कापी में लिखा है 10 फरवरी

महेश शर्मा ने कहा कि बेटी ने 10 जून को पेपर दिया था, जबकि कापी में 10 फरवरी लिखा हुआ है। साथ ही उत्तरपुस्तिका में हस्ताक्षर भी उसके नहीं थे। कापी पर परीक्षा कक्ष भी 19 के बदले 21 लिखा था। बेटी ने 25 में से 24 प्रश्न हल किए थे, लेकिन कापी में 15 प्रश्न लिखे गए हैं।

> मंडल के पास 12वीं की छात्रा की कापी बदलने की शिकायत मिली थी। जांच में उसके अंक बढ़ गए और वह पास हो गई। इस मामले में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
>
> **उमेश कुमार,**
> सचिव, माध्यम

> मेरी जानकारी में कापी बदलने का यह पहला मामला सामने आया है। इस साल केंद्रीय मूल्यांकन न करवाकर शिक्षकों को घर पर जांचने के लिए कापियां दी थीं। हो सकता है ऐसे में कापी बदल गई हो, लेकिन मंडल को इसकी जांच कर दोषी पर कार्रवाई करना चाहिए।
>
> **डा. भागीरथ कुमार शुक्ल,**
> पूर्व उपाध्यक्ष माध्यम